RNI NO. MPHIN/2022/85285
डाक पंजी.क्र. - MP/KDW/93/2026-28

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र

हलधर किसान

स्मार्ट किसान की पहली पसन्द Haldharkisankgn@gmail.com

वर्ष 5 अंक 02 (मासिक) अप्रैल पृष्ठ-8 मूल्य, 5 रुपये

क्या धोखा देगा मानसून : 30 प्रतिशत सूखे की आशंका, स्काईमेट का पूर्वानुमान

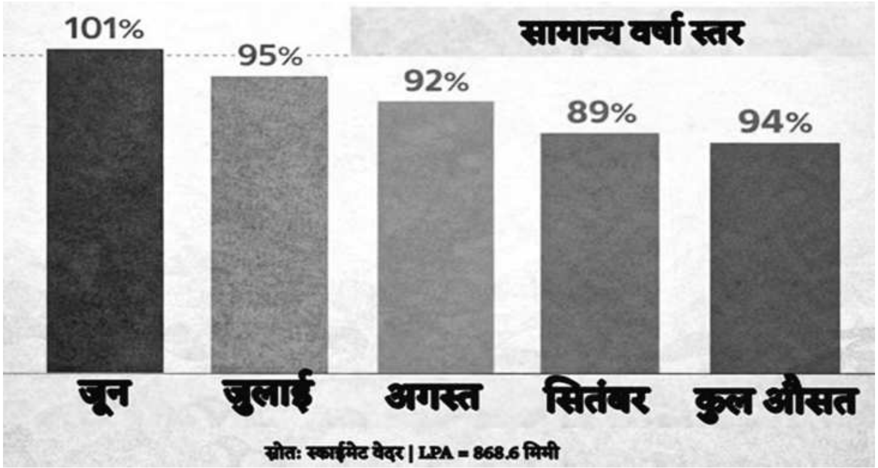

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

नई दिल्ली। खरीफ फसलों की बुआई से पहले मौसम विभाग से चिंताजनक सूचना सामने आई है। इस सूचना ने किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा दी है। निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर ने वर्ष 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून का पहला पूर्वानुमान जारी करते हुए इसे सामान्य से कम बताया है। स्काईमेट के प्रबंध निदेशक जतिन सिंह के अनुसार, पिछले डेढ़ वर्षों से सक्रिय ला नीना की स्थिति अब समाप्त हो रही है। प्रशांत महासागर ईएनएसओ.न्यूट्रल की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही, मानसून के शुरुआती चरण में ही अल नीनो के विकसित होने की संभावना है, जो सीजन के दूसरे भाग में और अधिक मजबूत हो सकता है।

अल नीनो एक समुद्री घटना है, जिसमें प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। इसका सीधा असर भारतीय मानसून पर पड़ता है और बारिश कमजोर तथा अनियमित हो जाती है। वैश्विक वित्तीय संस्था जेफरीज की रिपोर्ट के अनुसार इस बार अल नीनो के मजबूत होने की 60 प्रतिशत संभावना है। ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि जब भी अल नीनो मजबूत हुआ हैए भारत में बारिश में 15 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है।

मानसून में ऐसी रहेगी स्थिति

स्काईमेट ने मानसून के चारों महीनों के लिए अलग-अलग अनुमान जारी किए हैं। जून में मानसून की शुरुआत संतोषजनक रहने की उम्मीद है। एलपीए का 101 प्रतिशत वर्षा का अनुमान है, जो सामान्य श्रेणी में आता है।

जुलाई से बारिश में कमी आने लगेगी। इस महीने एलपीए का 95 प्रतिशत वर्षा होने की संभावना है।

अगस्त में बारिश घटकर एलपीए के 92 प्रतिशत पर आ सकती है। यह महीना कृषि के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

सितंबर में सीजन का यह अंतिम और सबसे कमजोर महीना रहेगा। केवल एलपीए का 89 प्रतिशत बारिश का अनुमान है।

हिंद महासागर की परिस्थितियां

मानसून पर केवल प्रशांत महासागर ही नहीं, बल्कि हिंद महासागर की परिस्थितियां भी गहरा प्रभाव डालती हैं। इंडियन ओशन डिपोल के इस वर्ष न्यूट्रल रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इससे मानसून की शुरुआत कुछ हद तक संतुलित रह सकती है, लेकिन अल नीनो के नकारात्मक प्रभाव को पूरी तरह निष्क्रिय करने में सक्षम नहीं होगा। यानी जून में राहत के बाद जुलाई से सितंबर तक स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी रहेगी।

सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य

स्काईमेट के अनुसार, देश के मध्य और उत्तर.पश्चिमी हिस्सों में बारिश की सबसे ज्यादा कमी देखी जा सकती है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अगस्त और सितंबर के दौरान सामान्य से काफी कम बारिश होने की आशंका है। इन राज्यों में खरीफ फसलों . विशेषकर धान, बाजरा और दलहन की खेती पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। पूर्वी और उत्तर.पूर्वी भारत में शेष देश की तुलना में बेहतर वर्षा की उम्मीद है। हालांकि, बारिश का वितरण असमान रहेगा।

देश में सूखे की स्थिति बनने की 30 प्रतिशत आशंका जताई गई है। सामान्य बारिश होने की संभावना केवल 20 प्रतिशत है। देश में सूखे की स्थिति बनने की 30 प्रतिशत आशंका जताई गई है। सामान्य बारिश होने की संभावना केवल 20 प्रतिशत है।

पूर्वानुमान के प्रमुख बिंदु

स्काईमेट की रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं सामने आई हैं जो स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करती हैं . कुल अनुमानित वर्षा एलपीए का 94 प्रतिशत यानी लगभग 868.6 मिमी रहने की संभावना है। देश में सूखे की स्थिति बनने की 30 प्रतिशत आशंका जताई गई है। सामान्य बारिश होने की संभावना केवल 20 प्रतिशत है। आईओडी के न्यूट्रल रहने से मानसून की शुरुआत तो ठीक रहेगी, लेकिन अल नीनो का असर जुलाई के बाद स्पष्ट दिखने लगेगा।

खेती और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर

भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आज भी मानसून पर निर्भर है। देश के आधे से अधिक कृषि योग्य क्षेत्र में सिंचाई के सीमित साधन हैं और वे वर्षा पर आश्रित हैं। ऐसे में कमजोर मानसून का सीधा असर खरीफ उत्पादन पर पड़ेगा। कम उत्पादन से खाद्य महंगाई बढ़ सकती है और ग्रामीण आय में गिरावट आ सकती है। ट्रैक्टर, उर्वरक और दोपहिया वाहनों जैसे ग्रामीण मांग से जुड़े क्षेत्रों पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ बिजली और कूलिंग क्षेत्र को इस स्थिति से फायदा मिल सकता है। कम बारिश और अधिक गर्मी से बिजली और एयर कंडीशनिंग की मांग बढ़ेगी।

पिछले वर्ष से तुलना करें तो दिखता है बड़ा अंतर

पिछले वर्ष यानी मानसून सीजन 2025 में देश में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर.पश्चिमी भारत में वर्षा का स्तर कई वर्षों में सबसे ऊंचा रहा था। इस बार का पूर्वानुमान उस सकारात्मक स्थिति के ठीक विपरीत है, जिससे किसानों और नीति निर्माताओं की चिंता स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है।

क्या करें किसान

विशेषज्ञों का सुझाव है कि इस पूर्वानुमान को देखते हुए सरकार को जल संरक्षण, सूखा प्रतिरोधी फसल किस्मों के प्रसार और फसल बीमा योजनाओं को समय रहते मजबूत करना चाहिए। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे कम पानी में उगने वाली फसलों की बुवाई को प्राथमिकता दें और मौसम विभाग के अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखें।

प्राकृतिक खेती पर पंजाब का फोकस, तैयार किया 1,388 करोड़ का कृषि प्लान

पराली प्रबंधन, प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण पर बड़े निवेश की तैयारी

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने 2026-27 के लिए 1,388 करोड़ का कृषि एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें पराली प्रबंधन, जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता दी गई है।

पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़ियां ने बताया कि यह वार्षिक योजना विभिन्न कृषि परियोजनाओं को लागू करने के लिए तैयार की गई है और इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। इस योजना के तहत सबसे बड़ा आवंटन 600 करोड़ का है, जो पराली प्रबंधन योजना के लिए रखा गया है। इसका उद्देश्य किसानों को सब्सिडी पर मशीनें उपलब्ध कराकर खेतों में पराली जलाने की समस्या का स्थायी समाधान निकालना है।

गिरते भूजल स्तर को देखते हुए ड्रॉप, मोर क्रॉप योजना के तहत पर 33.33 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे ड्रिप, स्प्रिंकलर और रेनगन जैसी तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पानी का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

फसल विविधीकरण पर जोर

धान जैसी अधिक पानी खपत वाली फसलों से हटाकर किसानों को मक्का, दालें और तिलहन जैसी फसलों की ओर प्रेरित करने के लिए 50.30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 8.25 करोड़ का बजट तय किया गया है। इसका उद्देश्य टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल कृषि प्रणाली विकसित करना है।

बीज सुधार और मशीनीकरण को बढ़ावा

राज्य सरकार ने बीज सुधार और कपास प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए 51.85 करोड़ आवंटित किए हैं। वहीं, कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए 95 करोड़ का बजट रखा गया है, जिससे खेती की उत्पादकता और दक्षता बढ़ेगी।

खरीफ सीजन से पहले 25 लाख मीट्रिक टन यूरिया आयात की तैयारी

हलधर किसान। एशियाई देशों में जारी संघर्ष के चलते उर्वरक आपूर्ति प्रभावित होने के बीच भारत ने घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख मीट्रिक टन यूरिया खरीदने की योजना बनाई है। सरकारी कंपनी इंडियन पोटाश लिमिटेड ने 1.5 मिलियन टन यूरिया के आयात के लिए टेंडर जारी किया है, जो पश्चिमी तट के जरिए आएगा। शेष 1 मिलियन टन पूर्वी तट से मंगाया जाएगा। सऊदी अरब और ओमान उसके सबसे बड़े सप्लायर रहे हैं।

टेंडर दस्तावेज के अनुसार, शिपमेंट 14 जून तक लोडिंग पोर्ट से रवाना होने की उम्मीद है। इच्छुक कंपनियों को 15 अप्रैल तक अपनी बोलियां जमा करनी होंगी। भारत नियमित रूप से वैश्विक टेंडरों के माध्यम से यूरिया खरीदता है। जून में मानसून के आगमन के साथ धानए मक्का और सोयाबीन की बुवाई शुरू होती है, जिसके लिए उर्वरकों की भारी जरूरत होती है।

मध्य पूर्व पर निर्भरता बनी चुनौती

भारत यूरिया, डीएपी और पोटाश जैसे उर्वरकों के लिए आयात पर निर्भर है। विशेषज्ञों के अनुसारए भारत के यूरिया आयात का 20-30 प्रतिशत और एलएनजी आयात का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा खाड़ी देशों से आता है, जो यूरिया उत्पादन के लिए जरूरी कच्चा माल है।

गैस संकट से उत्पादन प्रभावित

मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के बाद गैस आपूर्ति सीमित होने से भारत में यूरिया उत्पादन घट गया। पिछले महीने उत्पादन में करीब 6 से 7 लाख टन प्रति माह की कमी दर्ज की गई, हालांकि हाल के दिनों में गैस आपूर्ति में कुछ सुधार हुआ है।

वैश्विक बाजार में भी दबाव

उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि में आपूर्ति बाधित होने के कारण वैश्विक स्तर पर भी यूरिया की उपलब्धता सीमित है। इससे कीमतों में तेजी आई है और भारत का यह टेंडर अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए एक नया मूल्य मानक तय कर सकता है। पिछले नवंबर में भारत ने 418.40 डॉलर प्रति टन की दर से यूरिया खरीदा था, लेकिन वर्तमान हालात में कीमतें बढ़ चुकी हैं। ऐसे में इस बार के टेंडर में कीमतें और अधिक रहने की संभावना है। एक अन्य कदम में सरकार ने 6 अप्रैल से यूरिया बनाने वाले प्लांटों को प्राकृतिक गैस की सप्लाई मौजूदा 70-75 प्रतिशत से बढ़ाकर उनकी औसत खपत का 90 प्रतिशत करने का फैसला किया है।

उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि मार्च में घरेलू यूरिया उत्पादन घटकर 18 लाख टन रह गया। जबकि इसका सामान्य औसत 24 लाख टन है।

ग्रीष्मकालीन बुआई में मामूली बढ़त

58.29 लाख हेक्टेयर में बुआई का अनुमान दलहन-मोटे अनाज में रुझान, धान में गिरावट

हलधर किसान नई दिल्ली।

ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई में इस वर्ष मामूली बढ़त दर्ज हुई है। 3 अप्रैल तक कुल रकबा 58.29 लाख हेक्टेयर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.48 लाख हेक्टेयर अधिक है। इसमें दलहन और मोटे अनाज का रकबा बढ़ा है, जबकि धान और तिलहन का क्षेत्र घटा है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से मिली जानकारी अनुसार 3 अप्रैल तक मूंग की बुवाई 6.09 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गई थी, जो पिछले साल के 4.91 लाख हेक्टेयर से 1.18 लाख हेक्टेयर अधिक है। 3 अप्रैल तक मूंग की बुवाई 6.09 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गई थी, जो पिछले साल के 4.91 लाख हेक्टेयर से 1.18 लाख हेक्टेयर अधिक है। .

ग्रीष्मकालीन फसलों में सबसे उत्साहजनक प्रदर्शन दलहन का रहा। इस वर्ष दलहन का कुल रकबा 8.79 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 7.02 लाख हेक्टेयर से 1.77 लाख हेक्टेयर अधिक है। दलहन की सामान्य ग्रीष्मकालीन क्षेत्र सीमा 23.40 लाख हेक्टेयर है और 2025 का अंतिम रकबा 27.07 लाख हेक्टेयर रहा था।

3 अप्रैल तक मूंग की बुवाई 6.09 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गई थी, जो पिछले साल के 4.91 लाख हेक्टेयर से 1.18 लाख हेक्टेयर अधिक है। उड़द का रकबा भी 1.93 से बढ़कर 2.42 लाख हेक्टेयर हो गया, यानी 0.49 लाख हेक्टेयर की वृद्धि। अन्य दलहन में भी 0.11 लाख हेक्टेयर की मामूली बढ़त दर्ज की गई।

मोटे अनाज का कुल रकबा 11.64 लाख हेक्टेयर रहा, जो पिछले साल के 10.77 लाख हेक्टेयर से 0.87 लाख हेक्टेयर अधिक है। यह आंकड़ा सामान्य क्षेत्र 12.08 लाख हेक्टेयर के काफी करीब है। बाजरे का रकबा 3.15 से बढ़कर 3.91 लाख हेक्टेयर हो गयाए जो 0.76 लाख हेक्टेयर की वृद्धि को दर्शाता है। मक्का का रकबा 7.01 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 7.18 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। रागी का रकबा भी 0.16 से 0.21 लाख हेक्टेयर हुआ। हालांकि, ज्वार में 0.10 लाख हेक्टेयर की मामूली गिरावट देखी गई, जो 0.41 से घटकर 0.32 लाख हेक्टेयर रह गया है।

धान का रकबा पिछड़ा

ग्रीष्मकालीन फसलों में चिंता की बात यह है कि धान का रकबा इस वर्ष 30.12 लाख हेक्टेयर रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि के 32.59 लाख हेक्टेयर से 2.47 लाख हेक्टेयर कम है। धान की सामान्य ग्रीष्मकालीन क्षेत्र सीमा 31.49 लाख हेक्टेयर है। यह गिरावट कुल रकबे की बढ़त पर भारी पड़ रही है और आगामी हफ्तों में इस पर नजर रखना जरूरी होगा। बैठक में खरीफसीजन के लिए तैयारियां तेज करने के निर्देश भी दिए।

मूंगफली में राहत

तिलहन का कुल रकबा 7.74 लाख हेक्टेयर रहा, जो पिछले साल के 7.42 लाख हेक्टेयर से 0.31 लाख हेक्टेयर अधिक है। हालांकि, यह आंकड़ा सामान्य क्षेत्र 8.40 लाख हेक्टेयर से अभी भी कम है। मूंगफली का रकबा 4.20 से बढ़कर 4.59 लाख हेक्टेयर हो गया, जो 0.39 लाख हेक्टेयर की वृद्धि को दर्शाता है और यह सामान्य क्षेत्र के बराबर पहुंच गया है।

सूरजमुखी में भी 0.03 लाख हेक्टेयर की हल्की बढ़त रही। दूसरी तरफ तिल का रकबा 2.80 से घटकर 2.71 लाख हेक्टेयर पर आ गया है। 3 अप्रैल 2026 तक ग्रीष्मकालीन फसलों का रकबा 58.29 लाख हेक्टेयर रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि से थोड़ा अधिक है। सामान्य ग्रीष्मकालीन क्षेत्र 75.37 लाख हेक्टेयर और 2025 का अंतिम रकबा 83.92 लाख हेक्टेयर था। ऐसे में अभी बुआई का सीजन बाकी है और आने वाले हफ्तों में यह अंतर पाटा जा सकता है। दलहन और मोटे अनाज का बेहतर प्रदर्शन खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय दोनों के लिहाज से शुभ संकेत है।

241 शहरों में देश के सिर्फ14.9 फीसदी शहरों की आबोहवा साफ, 20 फीसदी शहरों में हालात चिंताजनक

नई दिल्ली। देश में वायु प्रदूषण का खतरा लगातार गहराता जा रहा है, जहां एक ओर मछलीपट्टनम और बर्नीहाट 283 एक्यूआई के साथ सबसे प्रदूषित शहर बनकर उभरे, वहीं दूसरी ओर मदिकेरी देश का सबसे स्वच्छ शहर रहाए जहाँ एक्यूआई महज 20 दर्ज किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ24 घंटों में कुछ शहरों में प्रदूषण में भारी उछाल आया है, और कई जगह प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा से कई गुना ज्यादा पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 241 शहरों के आंकड़े बताते हैं कि देश के सिर्फ14.9 फीसदी शहरों में ही हवा साफहैए जबकि करीब 20 फीसदी शहरों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। यह स्थिति साफ संकेत देती है कि देश में प्रदूषण का संकट उतार.चढ़ाव के बावजूद बना हुआ है और कई शहरों में हवा अब धीरे.धीरे स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति की ओर बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के 241 में से महज 36 शहरों में हवा बेहतर है। 157 शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर संतोषजनक (51.100 के बीच) रिकॉर्ड किया गयाए गौरतलब है कि 05 अप्रैल को यह आंकड़ा 151 दर्ज किया गया था। 42 शहरों में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में (101.200 के बीच) बनी हुई है।

06 अप्रैल को देश में आंध्रप्रदेश का मछलीपट्टनम और मेघालय का बर्नीहाट अधिक प्रदूषित शहर रहे। इस दौरान मछलीपट्टनम और बर्नीहाट में वायु गुणवत्ता सूचकांक 283 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। गौरतलब है कि इससे पहले 05 अप्रैल को जहां मछलीपट्टनम में एक्यूआई 75 जबकि बर्नीहाट में 152 दर्ज किया गया था। मतलब कि पिछले 24 घंटों में इन शहरों में प्रदूषण के स्तर में अच्छा-खासा इजाफा हुआ है। रुझानों में सामने आया है कि मछलीपट्टनम की हवा में ओजोन जबकि बर्नीहाट की हवा में प्रदूषण के महीन कण पूरी तरह हावी हैं। देखा जाए तो इन शहरों की फिजाओं में घुला जहर इतना ज्यादा है कि वो लोगों को बेहद बीमार बना देने के लिए काफी है।

क्या कहते हैं सरकारी आंकड़े

दूसरे शहरों की तुलना में आज आंध्रप्रदेश के मछलीपट्टनम और मेघालय के बर्नीहाट में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 283 दर्ज किया गया। गौरतलब है कि कल से इन दोनों शहरों में प्रदूषण के स्तर में इजाफा हुआ है। इस दौरान जहां मछलीपट्टनम में सूचकांक में 163 अंकों का जबकि बर्नीहाट में 131 अंकों का भारी उछाल दर्ज किया गया है। बता दें कि श्री गंगानगर में एक्यूआई 249 दर्ज किया गया थाए जहां आज एक्यूआई घटकर 241 पर पहुंच गया है। मतलब कि वहां पिछले 24 घंटों में सूचकांक में 8 अंकों का सुधार आया है। दिल्ली में कल से प्रदूषण में मामूली बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में जहां कल एक्यूआई 134 दर्ज किया गया थाए वो आज बढ़कर 135 पर पहुंच गया। मतलब कि पिछले 24 घंटों में सूचकांक में एक अंक का इजाफा हुआ है।

दिल्ली की तरह ही फरीदाबाद में भी कल से प्रदूषण में इजाफा हुआ है। फरीदाबाद में जहां कल वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 173 दर्ज किया गया था, जो आज बढ़कर 177 पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि वायु गुणवत्ता आज भी मध्यम श्रेणी में बनी हुई है।

प्रदूषण में उतार-चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। प्रदूषण के मामले में 06 अप्रैल को बर्नीहाट (असम) चौथे स्थान पर है, वहीं श्री गंगानगर (241) दूसरे, जबकि अंगुल (221) तीसरे स्थान पर है। अन्य प्रमुख शहरों से जुड़े आंकड़ों पर नजर डालें तो ग्वालियर में इंडेक्स 118, गाजियाबाद में 162, गुवाहाटी में 74, गुरुग्राम में 137, नोएडा में 159, ग्रेटर नोएडा में 192 पर पहुंच गया है।

इसी तरह मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया, जो प्रदूषण के संतोषजनक स्तर को दर्शाता है, जबकि लखनऊ में यह इंडेक्स 58, चेन्नई में 55, चंडीगढ़ में 59, हैदराबाद में 70, जयपुर में 138 और पटना में 112 दर्ज किया गया।

देश के जिन 36 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 या उससे नीचे यानी बेहतर रहा

क्या दर्शाता है वायु गुणवत्ता सूचकांक

देश में वायु प्रदूषण के स्तर और वायु गुणवत्ता की स्थिति को आप इस सूचकांक से समझ सकते हैं जिसके अनुसार यदि हवा साफ है तो उसे इंडेक्स में 0 से 50 के बीच दर्शाया जाता है। इसके बाद वायु गुणवत्ता के संतोषजनक होने की स्थिति तब होती है जब सूचकांक 51 से 100 के बीच होती है। इसी तरह 101.200 का मतलब है कि वायु प्रदूषण का स्तर माध्यम श्रेणी का है, जबकि 201 से 300 की बीच की स्थिति वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति को दर्शाती है। वहीं यदि सूचकांक 301 से 400 के बीच दर्ज किया जाता है जैसा दिल्ली में अक्सर होता है तो वायु गुणवत्ता को बेहद खराब की श्रेणी में रखा जाता है। यह वो स्थिति है जब वायु प्रदूषण का यह स्तर स्वास्थ्य को गंभीर और लम्बे समय के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद 401 से 500 की केटेगरी आती है जिसमें वायु गुणवत्ता की स्थिति गंभीर बन जाती है। ऐसी स्थिति होने पर वायु गुणवत्ता इतनी खराब हो जाती है कि वो स्वस्थ इंसान को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि पहले से ही बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए तो यह जानलेवा हो सकती है।

हलधर किसान औरंगाबाद. महाराष्ट्र में प्रदूषण फैलाने वाली उद्योगों पर लगाम कसने के लिए राज्य का पर्यावरण विभाग बड़ा कदम उठाने जा रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में भारी अनियमितताएं सामने आने के बाद सरकार ने बैंक गारंटी और जुर्माने की व्यवस्था में बदलाव करने का फैसला लिया है।

अधिकारियों के मुताबिक, एक समिति गठित की गई है जो अगले तीन महीनों में नई बैंक गारंटी और पेनल्टी स्ट्रक्चर की सिफारिश करेगी। इस बदलाव का मकसद उद्योगों की जवाबदेही बढ़ाना और पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है।

सीएजी रिपोर्ट में क्या सामने आया?

हाल ही में विधानसभा के बजट सत्र में पेश सीएजी रिपोर्ट में कई गंभीर खामियां उजागर हुईं। रिपोर्ट के अनुसार- 2,678 मामलों में 272.47 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भौतिक रूप से ली ही नहीं गई, जिससे उनका सत्यापन संभव नहीं हुआ। कई मामलों में गारंटी जब्त करने के आदेश लागू नहीं हो सके क्योंकि गारंटी जमा ही नहीं थी।

जब्त की गई 17.98 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग पर्यावरण सुधार के बजाय गलत तरीके से जमा कर दिया गया।

7.56 करोड़ रुपये की कंसेंट फीस की वसूली कम हुई।

339 उद्योगों पर लगाए गए 183.25 करोड़ रुपये के पर्यावरण मुआवजे की वसूली नहीं हो सकी और नोटिस बिना ठोस कारण के वापस ले लिए गए।

नए नियमों में क्या होगा बदलाव?

पर्यावरण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि नई व्यवस्था में प्रदूषण के स्तर के आधार पर बैंक गारंटी तय की जाएगी। ज्यादा प्रदूषित क्षेत्रों में उद्योगों पर अधिक सख्त गारंटी लागू होगी। उन्होंने कहा कि अब मनमाने दर नहीं होंगे। चंद्रपुर जैसे अधिक प्रदूषित इलाकों में ज्यादा गारंटी तय करने पर विचार हो रहा है।

ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम की तैयारी

सरकार एक ऑनलाइन सिस्टम भी लागू करने की योजना बना रही हैए जिससे बैंक गारंटी और जुर्माने की वसूली पर नजर रखी जा सके। इससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

2013 से नहीं बदली नीति

फिलहाल, उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में निवेश का 10ः बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होता है। यह नीति 2013 से लागू है और इसमें अब बदलाव की तैयारी की जा रही है।

उच्च स्तरीय बैठक के बाद फैसला

यह निर्णय पिछले हफ्ते पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद लिया गया। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुंडे ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा.निर्देशों और अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर तीन महीने में रिपोर्ट दें।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर

यह कदम अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें पर्यावरण नियामकों को प्रदूषण रोकने के लिए मुआवजा लगाने और बैंक गारंटी लेने का अधिकार दिया गया था। सरकार का कहना है कि नई नीति का उद्देश्य उद्योगों को जिम्मेदार बनाना है, जबकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नीति उद्योगों के लिए संतुलित और व्यवहारिक भी रहे।

विश्व चूहा दिवस विशेषः

रोग फैलाने से लेकर लाखों टन अनाज बर्बादी तक, चूहों पर नियंत्रण जरूरी

सेवानिवृत्त कीट वैज्ञानिक सतीश परसाई ने किया सतर्क

खरगोन। धर्मशास्त्र में चूहा भगवान गणेश का वाहन माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह जीव मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। विश्व चूहा दिवस के अवसर पर सेवानिवृत्त वरिष्ठ कीट वैज्ञानिक सतीश परसाई ने चूहों से होने वाले नुकसान और उनसे बचाव के उपायों पर विस्तृत जानकारी साझा की।

वैज्ञानिक श्री परसाई ने बताया कि चूहे न केवल प्लेग जैसी घातक बीमारियों के वाहक हैं, बल्कि इतिहास में ब्लैक डेथ जैसी महामारी के कारण करोड़ों लोगों की जान जा चुकी है। 14वीं शताब्दी में एशिया और यूरोप में फैली इस महामारी ने करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था।

वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार दुनिया के कुल स्तनधारियों में लगभग एक.तिहाई संख्या चूहों की है। भारत में इनकी संख्या मानव जनसंख्या से लगभग छह गुना अधिक मानी जाती है। चूहे हर साल देश में 6 से 10 प्रतिशत तक अनाज नष्ट कर देते हैं, जो लाखों टन खाद्यान्न और करोड़ों रुपये के नुकसान के बराबर है।

परसाई ने बताया कि चूहे जितना खाते हैंए उससे कई गुना अधिक अनाज अपने मल-मूत्र से खराब कर देते हैं। इनके कारण खेतों, गोदामों और घरों में भारी नुकसान होता है। यहां तक कि ये बिजली के तारों को भी कुतर देते हैंए जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं।

चूहों की प्रजनन क्षमता बेहद तेज होती है। एक जोड़ा एक वर्ष में हजारों और कुछ वर्षों में लाखों की संख्या में बढ़ सकता है। यही कारण है कि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो इनकी संख्या तेजी से बढ़ जाती है।

रोकथाम के उपायों पर दिया जाए जोर

श्री परसाई ने बताया कि चूहों से बचाव के लिए गोदामों को पक्का बनाना, पाइप और नालियों पर जालियां लगाना, खेतों में फसल को लंबे समय तक न छोड़ना जैसे उपाय बेहद जरूरी हैं। इसके अलावा पिंजरे, विषैले चारे और धूम्रक दवाओं का उपयोग भी प्रभावी माना जाता है। उन्होंने कहा कि जिंक फॉस्फाइड जैसे एकमात्रा विष और वारफारिन जैसे बहुमात्रा विष का उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। साथ ही एल्युमिनियम फॉस्फाइड जैसी दवाओं से बिलों में धूम्रक प्रक्रिया अपनाकर भी चूहों पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

ठोस प्रयास से ही हो सकेगा समाधान

परसाई ने जोर देकर कहा कि चूहों पर नियंत्रण के लिए व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक अभियान जरूरी है। गांव, खेत और शहर स्तर पर एक साथ प्रयास किए जाएं, तभी इनसे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।

2002 में हुई विश्व चूहा दिवस की शुरुआत

श्री परसाई ने बताया कि विश्व चूहा दिवस की शुरुआत 2002 में हुई थी, जिसका उद्देश्य चूहों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और उनके वैज्ञानिक महत्व को समझाना है। हालांकि आमजन के अनुभव इसके उलट हैं, जहां चूहे एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आते हैं।

उल्लेखनीय है कि इस विषय पर आकाशवाणी खंडवा द्वारा सतीश परसाई की एक विशेष बातचीत भी रिकॉर्ड की गई है, जिसमें उन्होंने विस्तार से जानकारी साझा की है।

नरवाई की आगः मजबूरी, सख्ती और समाधान के बीच जूझता किसान

हलधर किसान खरगोन.

जिले में इन दिनों खेतों में उठती नरवाई की आग सिर्फ फसल अवशेषों को नहीं जला रही, बल्कि किसानों की मजबूरी, प्रशासन की सख्ती और पर्यावरण की चिंता के बीच टकराव को भी उजागर कर रही है। हाल ही में गेहूं की नरवाई जलाने पर दो किसानों पर जुर्माना लगाए जाने के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में है।

देवली और कोठा बुजुर्ग के किसान गिरधारी राठौड़, महेश कुशवाह और दशरथ राठौड़ बताते हैं कि फसल कटाई के बाद खेत में बची नरवाई को हटाना आसान नहीं होता। यदि इसे मशीनों या मजदूरी के जरिए साफ किया जाए, तो खर्च कई गुना बढ़ जाता है। छोटे और मध्यम किसान पहले ही बढ़ती लागत, महंगे बीज, खाद और डीजल की मार झेल रहे हैं, ऐसे में अतिरिक्त खर्च उठाना उनके लिए संभव नहीं होता। यही वजह है कि वे मजबूरी में नरवाई जलाने का रास्ता चुनते हैं।

किसान मानते हैं कि नरवाई जलाने से मिट्टी के जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, लेकिन विकल्प महंगे होने के कारण वे असहाय महसूस करते हैं। किसानों का कहना है कि यदि सरकार कार्रवाई करती है, तो वैकल्पिक समाधान भी उपलब्ध कराने चाहिए। उल्लेखनीय है कि जिले में करीब 1 लाख 68 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की खेती की गई है, ऐसे में फसल कटाई के बाद बड़े पैमाने पर नरवाई प्रबंधन की चुनौती सामने आती है।

कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. आरके सिंह के अनुसार नरवाई को पशु चारे के रूप में उपयोग किया जा सकता है। साथ ही जैविक घोल के माध्यम से फसल अवशेषों को खाद में बदला जा सकता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। 2 किग्रा प्रोपेल या डी-कंपोजर को 2 किलो गुड़ और 200 लीटर पानी में घोलकर एक एकड़ में छिड़काव करने से दवाई कार्बनिक पदार्थ में बदल जाती है। उधर, कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा गोगावां विकासखंड के ग्राम उदयपुरा में किसान अनोखीलाल सोलंकी के खेत पर फसल अवशेष प्रबंधन का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मल्चर मशीन के जरिए अवशेषों को खेत में मिलाने की प्रक्रिया किसानों को समझाई गई।

प्रदर्शन के दौरान सहायक कृषि यंत्री मनीष मिश्रा ने बताया कि नरवाई जलाने से मिट्टी के सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, जिससे जमीन की उर्वरता लगातार घटती है। इसके साथ ही वायु प्रदूषण भी बढ़ता है।

- उप संचालक कृषि एसएस राजपूत ने बताया कि नरवाई जलाने पर 2500 रुपए से लेकर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है। साथ ही हार्वेस्टर मशीनों में स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है। फिलहाल स्थिति यह है कि एक तरफप्रशासन सख्ती कर रहा है, तो दूसरी ओर किसान आर्थिक दबाव में हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सख्ती के साथ.साथ किसानों को व्यवहारिक, सस्ते और प्रभावी विकल्प भी उपलब्ध कराए जाएं, ताकि समस्या का स्थायी समाधान निकल सके।

जल संरक्षण की दिशा में खरगोन को मिला प्रदेश में तीसरा स्थान

खरगोन निप्र। जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 जिले में जनभागीदारी और प्रशासनिक समन्वय के सतत प्रयासों से जिले ने प्रदेश स्तरीय डैशबोर्ड में तीसरा स्थान प्राप्त कर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है।

6 अप्रैल 2026 को जिले को प्रदेश स्तरीय डैशबोर्ड में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। उज्जैन एवं खंडवा के बाद जिले की यह रैंकिंग दर्ज की गई है, जबकि कसरावद विकासखंड भी प्रदेश के शीर्ष तीन ब्लॉकों में शामिल हुआ है। अभियान अवधि में जिले में कुल 7,284 कार्य स्वीकृत हुए, जिनमें से 4,039 कार्य पूर्ण होकर लगभग 55 प्रतिशत प्रगति हासिल की गई है।

वित्तीय रूप से, लगभग 147.82 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए, जिनमें से 116.05 करोड़ के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। अधिकांश कार्य मनरेगा के अंतर्गत संपादित किए गए हैं। इस अभियान में पंचायत एवं ग्रामीण विकासए नगरीय विकास, वन, जल संसाधन, कृषि, उद्यानिकी, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, राजस्व, संस्कृति एवं जनसंपर्क सहित लगभग 17 विभागों द्वारा समन्वित रूप से कार्य किया जा रहा है।

कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देशानुसार फील्ड अमले को जल गंगा संवर्धन कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वहीं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मिलिंद कुमार नागदेवे ने सतत मॉनिटरिंग एवं गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने वर्षा जल की प्रत्येक बूंद के संरक्षण को आवश्यक बताते हुए कहा कि इससे पेयजल, सिंचाई, निस्तार एवं भूजल स्तर में वृद्धि सुनिश्चित होगी। अमृत सरोवरों का उपयोग स्व.सहायता समूहों के माध्यम से मत्स्य पालन के लिए किए जाने की योजना है, जिससे आयवृद्धि के साथ स्थानीय रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान की पहल पर जयपुर से शुरू हुआ कृषि सुधारों का नया अध्याय

पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में किसानों की आय बढ़ाने, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रीशन पर तीन बड़े लक्ष्य

फार्मर आईडी से बदलेगा खाद, लोन और मदद का सिस्टम.

विकसित कृषि संकल्प अभियान और स्टेट एग्रीकल्चर रोडमैप से खेती की नई तस्वीर.

टीम एग्रीकल्चर, केंद्र-राज्य मिलकर करेंगे किसान कल्याण की योजनाओं का तेज़ क्रियान्वयन-केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

नई दिल्ली.

जयपुर में 7 अप्रैल को पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन से कृषि सुधारों के नए युग की मजबूत शुरुआत हुई। यहां केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया रोडमैप रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त किसान, समृद्ध भारत के विजन को धरातल पर उतारने के लिए क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस की यह नई श्रृंखला केंद्र और राज्यों के लिए साझा एक्शन.प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आई हैं।

जयपुर के होटल मैरियट में आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि एक दिन की औपचारिक रबी-खरीफ मीटिंग की जगह अब अलग- अलग एग्रो.क्लाइमेटिक ज़ोन के लिए गंभीर, विषय.आधारित क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही हैं। सम्मेलन की इस नई श्रृंखला की शुरुआत राजस्थान की धरती से होना उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण बताया, जहां राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान एक मंच पर जुटेए वहीं उद्घाटन सत्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे।

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने स्पष्ट किया कि यह केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी क्षेत्र की कृषि पर संपूर्णता से मंथन का प्रयास है, जिसमें पूरे दिन प्रजेंटेशन, वीडियो और विषयवार चर्चा के बाद ठोस निष्कर्ष और टू.डू लिस्ट के साथ राज्यों को आगे बढ़ने का रोडमैप तय किया जाएगा।

तीन प्रमुख लक्ष्य-

श्री चौहान ने भारतीय कृषि के लिए तीन मुख्य लक्ष्य रेखांकित किए। देश की खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय वृद्धि और पोषण सुरक्षा। उन्होंने कहा कि गेहूं और चावल में भारत के भंडार इतने हैं कि रखने की जगह तक की चुनौती है, लेकिन दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता अभी हासिल करनी है, ताकि खाद्य सुरक्षा पूरी तरह देश की अपनी उत्पादन क्षमता पर आधारित हो सके और आयात पर निर्भरता खत्म हो। उन्होंने दोहराया कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान उसकी आत्मा हैं, इसलिए किसानों की आय बढ़ाना, जीवन स्तर सुधारना और खेती को आसान बनाना सरकार की प्राथमिकता है, साथ ही जनता को पोषक आहार उपलब्ध कराने के लिए पोषण सुरक्षा को नीति का अनिवार्य अंग बताया।

फार्मर आईडी और डिजिटल एग्रीकल्चर की बड़ी झलक

केंद्रीय कृषि मंत्री ने फार्मर आईडी को आने वाले समय की सबसे उपयोगी व्यवस्था बताते हुए कहा कि एक प्रमाणित डिजिटल प्रोफाइल के आधार पर बैंक लोन से लेकर सरकारी मदद तक सब कुछ तेज़ और पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुँचेगा। उन्होंने बताया कि कुछ राज्यों में फार्मर आईडी के माध्यम से कुछ ही दिनों में हजारों करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं और आगे खाद वितरण जैसी संवेदनशील व्यवस्था भी किसान की भूमि और बोई गई फसल के आधार पर फार्मर आईडी से ही लिंक की जाएगी, ताकि सस्ता खाद डायवर्जन रोका जा सके।

श्री चौहान ने बताया कि दलहन और तिलहन की खरीद के माध्यम से कृषि विभाग द्वारा और गेहूं-चावल की खरीद खाद्य विभाग द्वारा की जा रही है तथा राज्यों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के अनुरूप ही खरीद की स्वीकृति दी गई है, लेकिन समयबद्ध खरीद सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि चने, मसूर और तुअर की 100 प्रतिशत खरीद की जाएगी। जहाँ फिजिकल खरीद संभव नहीं है, वहाँ मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के मॉडल पर सरसों और सोयाबीन में भावांतर भुगतान के माध्यम से एमएसपी और बाजार भाव के अंतर की भरपाई किसानों के खातों में सीधे की जा सकती है।

उन्होंने आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों में अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिरती कीमतों की चुनौती का उल्लेख करते हुए एमआईएस व्यवस्था की उपयोगिता समझाई, जिसमें मॉडल रेट और बाजार भाव के अंतर का भुगतान सीधा किसान को किया जा सकता है, जिसमें 50 प्रतिशत हिस्सा केंद्र और 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी, साथ ही जिन राज्यों की एजेंसियाँ किसानों की उपज को उत्पादन क्षेत्र से बड़े शहरों तक ले जाना चाहेंगी, उनके लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देने का निर्णय भी साझा किया।

जो भी राज्य समय.सारिणी और कार्यक्रम भेजेंगे, वहाँ भारत सरकार वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों की टीम भेजकर अभियान को गति देगी। राजस्थान के संदर्भ में उन्होंने आईसीएआर के वैज्ञानिकों की विशेष टीम भेजने की घोषणा की, जो राज्य के तय कार्यक्रम में खेत स्तर पर वैज्ञानिक सलाह और नवाचारों का विस्तार करेगी।

हाल के मौसमीय असंतुलन और नुकसान का जिक्र करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यों से नुकसान के सही आंकलन और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया, ताकि प्रभावित किसानों को पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि ज़मीन पर सक्रिय भूमिका राज्यों की होगी और केंद्र की ओर से किसानों को भरपूर सहयोग देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

विश्व स्वास्थ्य दिवस के संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी के स्वस्थ भारत के संदेश का हवाला देते हुए अपील की कि तेल और भोजन की मात्रा में संयम के साथ सभी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है और कृषि नेतृत्व को भी फिट रहकर किसानों की सेवा में जुटे रहने की प्रेरणा दी।

रायसेन में 11 से तीन दिवसीय कृषि महाकुंभ किसानों को मिलेंगे बहु-आयामी आय के नए अवसर

हलधर किसान नई दिल्ली

मध्य प्रदेश के रायसेन में 11 अप्रैल से तीन दिन कृषि का महाकुंभ की शुरुआत होगी। इस महते आयोजन में फसल के साथ-साथ डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, बकरी पालन, एफपीओ - मार्केटिंग और ग्रामीण महिलाओं की आजीविका के अवसरों पर विशेष ध्यान होगा, ताकि किसानों की आय के अनेक मजबूत स्तंभ तैयार हो सकें।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन में बीज से बाजार और मछली से मोती तक, पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वैल्यू-चेन को एक ही मंच पर जोड़ा जाएगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि रायसेन में 11 से 13 अप्रैल तक होने वाले इस महोत्सव में उत्पादन, पशुपालन, प्रसंस्करण, मार्केटिंग और उद्यमिता की पूरी वैल्यू-चेन को एक साथ रखा जाएगा ताकि किसान खेत से लेकर बाज़ार और निर्यात तक की पूरी यात्रा को एक ही जगह समझ सकें।

रायसेन का दशहरा मैदान तीन दिनों के लिए लाइव डेमो, तकनीकी सत्र, प्रशिक्षण श्रृंखला और बिज़नेस-मीटिंग्स का केंद्र बनेगा, जहां वैज्ञानिकख स्टार्ट-अप, एफपीओ, स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण उद्यमी आमने-सामने संवाद करेंगे। इस उन्नत कृषि महोत्सव में पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा राज्य सरकार की ओर से आयोजित पशुधन प्रदर्शन में गिर, साहीवाल, थारपारकर, मालवी जैसी उन्नत गाय नस्लें तथा जमुनापारी, बारबरी, सिरोही, बीटल, सोजत जैसी दुग्ध और मांस दोनों के लिए उपयुक्त बकरी नस्लें प्रदर्शित की जाएँगी। वहीं कड़कनाथ जैसी विशिष्ट पोल्ट्री नस्ल किसानों को उच्च मूल्य वाली मार्केट से जोड़ने का रास्ता दिखाएगी। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई के माध्यम से पशु-स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण, पोषण प्रबंधन, प्रजनन एवं नस्ल सुधार पर विशिष्ट जानकारी दी जाएगी, जिससे छोटे एवं सीमांत पशुपालकों को कम लागत में अधिक उत्पादकता के व्यावहारिक उपाय सीखने का मौका मिलेगा। डेयरी-कोऑपरेटिव, चारा प्रबंधन, गोबर-आधारित ऊर्जा और ऑर्गेनिक-इनपुट जैसे विषयों पर भी मार्गदर्शन दिया जाएगा, ताकि पशुधन को खेती के साथ जोड़कर चक्रीय और टिकाऊ कृषि-मॉडल तैयार हो सकें।

मत्स्य, एक्वाकल्चर और जल-आधारित उद्यम

मत्स्य विभाग और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा बायोफ्लॉक, पुनरावर्ती एक्वाकल्चर प्रणाली, एक्वापोनिक्स, सजावटी मछली पालन और मोतीपालन के लाइव मॉडल दिखाए जाएँगे, ताकि किसान और युवा कम पानी व कम स्थान में भी उच्च आय वाले आधुनिक त्स्य-मॉडलों को नज़दीक से समझ सकें।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, राष्ट्रीय मत्स्य विकास कार्यक्रम, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी, जिससे किसान खेत के साथ तालाब, रिसाइक्लिंग टैंक या एक्वापोनिक्स यूनिट के रूप में जल-आधारित उद्यम भी शुरू कर सकें और साल भर आय के नए स्रोत बन सकें।

50 प्लस एफपीओ और मार्केटिंग डिवीजन

मार्केटिंग डिवीजन के तहत 50 से अधिक किसान उत्पादक संगठन भाग लेंगे, जो जीआई टैग चिन्नौर चावल, शरबती गेहूँ, मिलेट आधारित उत्पाद कोदो, कुटकी, विभिन्न दालें, बेसन, सोया उत्पाद, हल्दी-लहसुन-मोरिंगा पाउडर, सरसों-अलसी तेल, शहद, अचार, गुड़, गुड़ पाउडर, गुड़ कैंडी, मूंगफली चिक्की और तिल-लड्डू जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री करेंगे, जिससे स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और बेहतर दाम मिल सके। 12 अप्रैल को होने वाले एफपीओ सम्मेलन में संगठन-प्रबंधन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, कोल्ड-चेन, लॉजिस्टिक्स और ई-ट्रेड प्लेटफॉर्म्स पर विस्तृत चर्चा होगी, ताकि छोटे किसान उत्पादक संगठन ई-कॉमर्स और आधुनिक रिटेल चैनल के माध्यम से लोकल-टू-नेशनल की यात्रा तेज़ी से पूरी कर सकें।

एलपीजी का विकल्प हो सकती है बायोगैस

भारत आज ऊर्जा परिवर्तन के एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। एक ओर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं ने करोड़ों घरों तक एलपीजी पहुंचाकर स्वच्छ ईंधन की क्रांति लाई है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती आयात निर्भरता, कीमतों में उतार.चढ़ाव और वैश्विक भू.राजनीतिक संकटों ने देश की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। हाल के समय में पश्चिम एशिया के तनाव के कारण एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होने की घटनाओं ने इस चिंता को और गहरा किया है। अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है। निःसंदेह,ए यह स्थिति भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देश के लिए एक चेतावनी है कि अब ऊर्जा सुरक्षा के प्रश्न को टालना संभव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संकटों का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ता है। पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है और घरेलू रसोई तक प्रभावित होती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के विकल्प तलाशें। इसी संदर्भ में बायोगैस एक मजबूत और टिकाऊ समाधान के रूप में उभरती है। बायोगैस जैविक कचरे-जैसे गोबर, कृषि अवशेष, रसोई कचरा आदि से उत्पन्न गैस है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन होती है। यह गैस खाना पकाने, बिजली उत्पादन और वाहन ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल की जा सकती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में बायोगैस की अपार संभावनाएं हैं। गांवों में पशुधन और जैविक कचरे की उपलब्धता इसे एक व्यावहारिक विकल्प बनाती है। गांवों में छोटे और मध्यम आकार के बायोगैस प्लांट स्थापित कर स्थानीय स्तर पर गैस का उत्पादन किया जा सकता है। इससे एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता कम होगी। आधुनिक तकनीक के माध्यम से बायोगैस को शुद्ध कर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाया जा सकता है, जो एलपीजी और सीएनजी का प्रभावी विकल्प है। गोबर.धन योजना और एसएटीएटी जैसी योजनाएं बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा दे रही हैं। इनके माध्यम से किसानों और उद्यमियों को आर्थिक सहायता और बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। शहरों में निकलने वाले जैविक कचरे को बायोगैस में बदलकर न केवल ऊर्जा पैदा की जा सकती है, बल्कि कचरा प्रबंधन की समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। भारत में एलपीजी की सालाना खपत लगभग 28-31 मिलियन टन के आसपास है। भारत में एलपीजी का घरेलू उत्पादन लगभग 10-12 एमएमटी प्रति वर्ष है। यानी कुल मांग का केवल 35-40 प्रतिशत ही देश में बनता है। भारत को हर साल लगभग 18-22 एमएमटी एलपीजी आयात करनी पड़ती है। यानी 60-65 प्रतिशत एलपीजी आयात पर निर्भरता। भारत आधा से ज्यादा एलपीजी बाहर से खरीदता है। आयात का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। इसलिए हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे संकट भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधा खतरा हैं। भारत में अभी लगभग 132 सीबीजी प्लांट चल रहे हैं। इनकी कुल उत्पादन क्षमता लगभग 920 टन प्रतिदिन है। यानी अभी बायोगैस का योगदान 1 प्रतिशत से भी कम है। भारत 20 एमएमटी सीबीजी बना सकता है। कुल संभावित क्षमता कचरा, गोबर, अवशेष की। कुल क्षमता लगभग 60 एमएमटी तक मानी जाती है। इसका मतलब भारत अपनी पूरी एलपीजी जरूरत (30 एमएमटी) बायोगैस से पूरा कर सकता है। फिलहाल अभी लगभग 300 से अधिक नए प्लांट निर्माणाधीन हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार भारत में 2030 तक बायोगैस उत्पादन 7 गुना तक बढ़ सकता है। बायोगैस न केवल सस्ती है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है, जैविक खाद भी मिलती है और किसानों की आय बढ़ती है। साथ ही, यह स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा हालांकि, बायोगैस के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी हैं-जैसे शुरुआती निवेश, तकनीकी जानकारी की कमी और जागरूकता का अभाव।

14 को खरमास की विदाई, फिर से शुरु होंगे मांगलिक कार्य

19 और 20 अप्रैल दो दिन रहेंगे, अक्षय तृतिया के अबुझ मुहुर्त

ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप जैन(सोनी) अजमेर

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

एक माह से मांगलिक कार्यों पर लगी रोक जल्द हटने वाली है। यह रोक हटते ही एक बार फिर शादियों सहित अन्य मांगलिक कार्यों की धूम शुरु हो जाएगी।

ज्योतिषाचार्य सुदीप सोनी अजमेर के अनुसार सनातन धर्म में वैदिक पंचांग के अनुसार मांगलिक कार्यों को संपन्न करने के लिए ग्रह नक्षत्रों की दशा को विशेष महत्व दिया जाता है। इनके उदय और अस्त होने से शुभ कार्य प्रभावित हो जाते हैं। खरमास भी ग्रहों की युति से बना ऐसा ही समय काल है, जिसमें मांगलिक कार्य प्रतिबंधित हो जाते हैं।

15 मार्च से सूर्य के मीन राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास शुरू हुए थे, जो कि 14 अप्रैल मंगलवार को सुबह 9.38 बजे सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ खरमास समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही विवाह, गृह प्रवेश, लग्न, शुभ समारोह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, व्यवसाय आरंभ के साथ नए कार्यों का पुनः शुभारंभ हो जाएगा।

ज्योतिषाचार्य डॉ.सोनी ने बताया कि ग्रहों के राजा सूर्य अलग अलग राशियों में संचरण करते हैं किसी राशि में सूर्य का प्रवेश संक्रांति नाम से जाना जाता है। सूर्य के धनु अथवा मीन राशि में आने से खरमास नाम का एक विशेष तपशील काल बनता है, जिसे देव कार्यों के लिए तो श्रेष्ठ माना गया है। परंतु सांसारिक शुभ कार्यों हेतु निषेध माना गया है। मान्यताओं के अनुसार, खरमास के कालखंड में सूर्य की तेजस्वी ऊर्जा कुछ मंद मानी जाती है। सूर्य को नवग्रहों का अधिपति और आत्मबल का प्रमुख कारक माना गया है, इसलिए उनकी पूर्ण कृपा के अभाव में किए गए मांगलिक कार्य अपेक्षित सफलता प्रदान नहीं कर पाते।

इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति भी अपनी संपूर्ण शुभ शक्ति का प्रभाव नहीं दिखा पाते, जिसके कारण शुभ आयोजनों का फल अधूरा या कमजोर रह सकता है। इस कारण से खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं जाते। विवाह आयोजनों की शुरुआत के पहले ही धर्मशाला, रिसॉर्ट, मैरेज हॉल, टैंट- लाईट, केटरिंग, पंडित, बैंड-बाजा, डीजे, मेहंदी आदि की बुकिंग कर दी गई है।

ये हैं शुभ मुहूर्त

अप्रैल.20, 21,25, 26, 27, 29, 30

मई. 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 14 को विवाह मुहुर्त है।

जून में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27और 29 जून. को मुहुर्त है। इसी तरह जुलाई में 1, 6, 7 और 11 जुलाई को मांगलिक आयोजन के मुहुर्त है।

अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त

वैशाख शुक्ल की तृतीया को अक्षय तृतीया है। इस बार तृतीया तिथि का आरंभ 19 अप्रैल को सुबह 10 बजकर 49 मिनट पर होगा और समापन 20 अप्रैल को सुबह 7 बजकर 27 मिनट पर होगा। उदया तिथि के अनुसार। अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल को मनाया जाएगा।20 अप्रैल को भी अक्षय तृतीया मना सकते हैं। इस दिन बिना पंचाग देखें शादियां की जा सकती हैं।

वर्ग पहेली नं. 21 बाएं से दाएं

1. छिपाछिपाई का बच्चों का खेल (5)
5. ओखली (3)
6. समय, अवधि (3)
8. भगिनी, सहोदरा (3)
9. रोग की गाँठ (3)
11. वेतन पर काम करने वाला (5)
15. संभव है कि (5)
18. सोना, स्वर्ण (3)
20. कफन का बक्सा (3)
21. अनाथ (3)
23. दूध से बनी एक मिठाई (3)
25. खतरे में डाल देने वाला (5)

ऊपर से नीचे.

1. अक्ष, दृष्टि (2)
2. हड़बड़ी, घबराहट (4)
3. नब्बे व चार की संख्या (4)
4. तथा, एवं (2)
5. अनुपजाऊ, बंजर (3)
6. शांति (3)
7. एक वाद्ययंत्र (3)
10. सुगंध (3)
12. नियत (2)
13. खाना (3)
14. समाप्ति (2)
15. बचत (3)
16. संदेह (3)
17. वाहनों.का.आवागमन (4)
18. कैंची से काटना (4)
19, रद्दी का काम करने वाला (3)
22. बाण (2)
24. बगुला (2)

■	१	२		३		■	४	■
५			■		■	६		७
	■	८			■		■	
९	१०		■	११	१२		१३	
■		■	१४	■		■		■
१५		१६		१७	■	१८		१९
	■		■	२०			■	
२१	२२		■		■	२३	२४	
■		■	२५					■

वर्ग पहेली नंबर 20 का हल

■	१ रा	२ ज	नी	३ ति	क	■	४ चो	■
५ वि	ज	य	■	क	■	६ म	री	७ ज
शा	■	८ का	व	ड़	■	ही	■	मी
९ ल	१० ह	रा	■	११ म	१२ नो	न	१३ य	न
■	रे	■	१४ श्रे	■	न	■	कृ	■
१५ य	क	१६ ब	य	१७ क	■	१८ अं	त	१९ र
मृ	■	धि	■	२० स	बू	त	■	से
२१ ना	२२ य	क	■	ब	■	२३ रं	२४ जि	श
■	श	■	२५ नी	ल	ग	ग	न	■

तीन राज्यों में एमएसपी पर 11,698 करोड़ रुपये की दलहन-तिलहन खरीद को मिली मंजूरी

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी 2025-26 सीजन के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 18 लाख मीट्रिक टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद को मंजूरी दी है। इस पर कुल करीब 11,698 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए रबी 2026 सीजन के लिए एमएसपी पर 13,082 मीट्रिक टन चना और 3,60,528 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की अनुमति दे दी है। यह खरीद पीएसएस के अंतर्गत की जाएगी और इन स्वीकृतियों का कुल एमएसपी मूल्य 2,312.12 करोड़ रुपये से अधिक होगा।

उत्तर प्रदेश में चना, मसूर और सरसों की खरीद

उत्तर प्रदेश के पीएसएस प्रस्ताव के अंतर्गत रबी 2026 सीजन के लिए एमएसपी पर 2,24,000 मीट्रिक टन चना की खरीद को स्वीकृति दे दी गई है, जिसका एमएसपी मूल्य 1,316 करोड़ रुपये है। मसूर की 6,77,000 मीट्रिक टन की पूरी मांग 100 प्रतिशत को स्वीकृति दी गई है, जिस पर एमएसपी मूल्य 70,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से 4,739 करोड़ रुपये होगा। सरसों के लिए स्वीकृत मात्रा 5,30,000 मीट्रिक टन का एमएसपी मूल्य 62,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से 3,286 करोड़ रुपये होगा।

कर्नाटक में कुसुम की खरीद

कर्नाटक में रबी 2025-26 सीजन के दौरान कुसुम (सैफ्लावर) की फसल के लिए पीएसएस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत स्वीकृत मात्रा 6,923 मीट्रिक टन की उपज एमएसपी पर खरीदी जाएगी। राज्य की तरफसे भेजे गए प्रस्ताव में 25 प्रतिशत मात्रा (6,923 मीट्रिक टन) को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2025.26 के लिए कुसुम का एमएसपी 65,400 रुपये प्रति मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है, जिससे कुल एमएसपी मूल्य 45.27 करोड़ रुपये बनता है।

हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के लिए स्वीकृत पीएसएस प्रस्तावों के माध्यम से, चना, मसूर, सरसों और कुसुम जैसी महत्वपूर्ण दलहन और तिलहन फसलों की एमएसपी पर वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित खरीद सुनिश्चित की जाएगी। इससे न केवल किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के देश में खाद्य और पोषण सुरक्षा बढ़ाने, तिलहन और दलहन उत्पादन बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के संकल्प को भी बल मिलेगा। इसके साथ ही, राज्यों द्वारा पीओएस आधारित खरीद की व्यवस्था पहले से ही सुदृढ़ होने के कारण, किसानों के लिए पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आईसीएआर ने बनाई टास्क फोर्स

हलधर किसान नई दिल्ली. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वैश्विक स्तर पर उभरती चुनौतियों का सामना करने और कृषि क्षेत्र के लिए रणनीतिक समाधान तैयार करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है।

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव एवं आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एमएल जाट की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में राष्ट्रीय खाद्य और कृषि इनपुट सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया गया।

किसानों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मेरा गांव मेरा गौरव अभियान के दायरे को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस पहल के तहत 100 आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी और मौजूदा संस्थागत ढांचे का उपयोग करते हुए किसानों को समग्र कृषि पैकेज उपलब्ध कराया जाएगाए जिससे जमीनी स्तर पर भरोसा बढ़े।

संतुलित उर्वरक और जैव.इनपुट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गेहूं और धान जैसी प्रमुख फसलों में उर्वरक खपत का जिला.वार आकलन किया जाएगा, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

भूमि उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए मोटा अनाज उगाने वाले क्षेत्रों की विस्तृत मैपिंग की जा रही है। इसके साथ ही कम उत्पादक धान क्षेत्रों में उच्च मूल्य वाली वैकल्पिक गतिविधियो, जैसे इको.फिशरीज को बढ़ावा देने की योजना है। इससे खरीफसीजन में किसानों की आय बढ़ाई जा सकेगी।

तकनीकी और यांत्रिक हस्तक्षेप

कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए डायरेक्ट सीडिंग ऑफराइस जैसी तकनीकों पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट को मजबूत कर किसानों को रियल.टाइम सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विषय से संबंधित प्रभाग में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो साप्ताहिक प्रगति की निगरानी करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों के लिए समेकित कार्य योजना तैयार करेंगे। यह विशेष टास्क फोर्स फीडबैक तथा आंतरिक विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए सरकार को डेटा.आधारित सुझाव प्रदान करेगी।

अमेरिका.इस्राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से उर्वरक आपूर्ति हो सकती है बाधित, खेती पर पड़ेगा असर

हलधर किसान, नई दिल्ली। अमेरिका- इसराइल और ईरान के बीच युद्ध के चलते बढ़ते तनाव के कारण देश में उर्वरक का खतरा मंडरा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघर्ष लंबा खिंचता है तो उर्वरक आपूर्ति बाधित होने से खेती पर असर पड़ सकता है।

रिसर्च एजेंसी बीएमआई के अनुसार, भारत में उर्वरकों की मांग का महत्वपूर्ण समय मार्च के अंत से अप्रैल तक होता है, ऐसे में यह संकट बेहद संवेदनशील समय पर सामने आया है। जून से फॉस्फेट उत्पादन का मुख्य सीजन शुरू होता है, जिससे आपूर्ति पर दबाव और बढ़ सकता है।

गैस आपूर्ति बाधित, उत्पादन पर असर

विशेषज्ञों का कहना है कि कतर से प्राकृतिक गैस आपूर्ति बाधित होने के कारण भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में कई उर्वरक संयंत्रों को उत्पादन बंद करना पड़ा है। वहीं, मिस्र को भी इस्राइल से गैस आपूर्ति प्रभावित होने के कारण महंगे एलएनजी बाजार का सहारा लेना पड़ रहा है।

उर्वरक उपयोग में कमी का खतरा

यदि यह संघर्ष एक महीने से अधिक चला, तो उर्वरक उपयोग में कमी आ सकती है, जिससे फसल उत्पादन प्रभावित होगा। इसके साथ ही, संभावित अल नीनो के कारण सूखे जैसे हालात बनने की आशंका भी जताई गई है, जो उत्पादन को और प्रभावित कर सकता है।

होर्मुज जलडमरूमध्य बना अहम कारक

होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिये वैश्विक उर्वरक और उसके कच्चे माल की लगभग 30 प्रतिशत सप्लाई होती है। इस मार्ग पर असर पड़ने से गैस, अमोनिया और यूरिया के उत्पादन पर सीधा असर पड़ा है और कीमतों में तेजी आई है।

यूरिया और अन्य खाद की कीमतें बढ़ी

विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले एक महीने में यूरिया की कीमतों में करीब 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा फॉस्फेट उर्वरकों और सल्फर की आपूर्ति पर भी असर पड़ा है, जो उर्वरक उत्पादन के लिए जरूरी घटक हैं।

किसानों के सामने विकल्प सीमित

विश्लेषकों के मुताबिक, किसानों के पास अब तीन ही विकल्प बचते हैं . महंगे दाम पर खाद खरीदनाए उपयोग कम करना और कम उत्पादन स्वीकार करना, या कम उर्वरक वाली फसलों की ओर रुख करना। इन सभी विकल्पों का असर अनाज की कीमतों पर पड़ेगा।

भारत पर क्यों पड़ रहा है ज्यादा असर

भारत वैश्विक उर्वरक खपत में लगभग 15 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। दक्षिण एशिया में उर्वरक खपत के मामले में भारत की यह हिस्सेदारी 80 प्रतिशत तक है। हमारे यहां यूरिया का उपयोग सबसे अधिक होता है और सरकार किसानों को सब्सिडी के जरिये इसकी खरीद में मदद करती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही होर्मुज जलडमरूमध्य जल्द खुल जाए, लेकिन उर्वरक उत्पादन और सप्लाई चेन को सामान्य होने में कई सप्ताह लग सकते हैं।

अमरूद के बागों में तेजी से फैल रहा ये उकठा रोग, आईसीएआर ने शुरू किया बचाव अभियान

हलधर किसान . भोपाल।

अमरूद बाग इन दिनों उकठा रोग की चपेट में आ रहे है। निमेटोड संक्रमण के कारण फसल उत्पादन गंभीर रूप से प्रभावित होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि वैज्ञानिकों ने रोग एवं कीटों के समेकित प्रबंधन के जरिए अमरूद के प्रभावित बागों को सुधारने का अभियान शुरू किया है।

वैज्ञानिकों के अनुसार फफूंद जनित उकठा रोग कई दशकों से अमरूद उत्पादन के लिए बड़ी बाधा रहा है। वर्ष 2014.16 के आसपास अमरूद नर्सरी में जड़.ग्रंथि निमेटोड के प्रवेश ने स्थिति और खराब कर दी। यह संक्रमण रोपण सामग्री के जरिए कई क्षेत्रों में फैल गया, जिससे संक्रमित बागों की उत्पादकता घट गई और कई नए बाग नष्ट हो गए।

आईसीएमआर का हस्तक्षेप और सुधार प्रयास

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत सीएसआईआर.राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने एमआईडीएच परियोजना के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्रों में सुधार कार्य शुरू किए हैं। संस्थान लखनऊ और बदायूं के अधिक प्रभावित बागों और नर्सरी को नीमैटोड मुक्त बनाने के लिए दीर्घकालिक उपचार और निगरानी कर रहा है।

समेकित रोग प्रबंधन रणनीति

संस्थान द्वारा अपनाई गई योजना में संक्रमित मिट्टी का नेमेटिसाइड से उपचार किया जा रहा है। इसके बाद ट्राइकोडरमा या बैसिलस जैसे जैविक एजेंटों का उपयोगए नीम खली या कम्पोस्ट के साथ मिलाकर किया जाता है। साथ ही, ऐसे इंटरक्रॉप्स से बचने की सलाह दी गई है जो नीमैटोड के प्रति संवेदनशील हों।

किसानों के लिए सहयोग और अपील

परियोजना के तहत उपचार की सामग्री लागत संस्थान द्वारा वहन की जा रही है और प्रशिक्षित विशेषज्ञों की निगरानी में किसानों द्वारा इसका प्रयोग कराया जा रहा है। संस्थान ने किसानों से अपील की है कि वे अपने बागों के उपचार के लिए संपर्क करें, ताकि संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके।

अमेरिका में गेहूं से दूरी, सोयाबाबीन में रुचि दिखा रहे किसान

अमेरिका में गेहूं का रकबा सदी के न्यूनतम स्तर पर, यूएसडीए की रिपोर्ट

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

नई दिल्ली। अमेरिकी कृषि विभाग की मार्च की प्रॉस्पेक्टिव प्लांटिंग्स रिपोर्ट के अनुसार, कुल गेहूं का बोया गया क्षेत्र 4.38 करोड़ एकड़ रहने का अनुमान है, जो 2025 की तुलना में 3 प्रतिशत कम है। यदि यह अनुमान सही साबित होता है, तो यह 1919 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद अमेरिका में गेहूं का सबसे कम रकबा होगा।

आंकड़ों पर गौर करें तो अमेरिका में 2026 में गेहूं की खेती का रकबा पिछली एक सदी से भी अधिक समय के निचले स्तर पर पहुंच सकता है। यह बदलाव फसल पैटर्न में एक संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, जहां किसान धीरे-धीरे गेहूं से दूरी बना रहे हैं।

यह गिरावट गेहूं की सभी प्रमुख श्रेणियों में देखी जा रही है। विंटर व्हीट का रकबा 3.24 करोड़ एकड़ आंका गया है, जो पिछले वर्ष और पहले के अनुमानों से कम है। स्प्रिंग व्हीट का क्षेत्रफल 94.2 लाख एकड़ रहने का अनुमान है, जो सालाना आधार पर 6 प्रतिशत कम है। ड्यूरम व्हीट में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है, जो 11 प्रतिशत घटकर 19.5 लाख एकड़ रह गया है।

यूएसडीए ने मार्च 2024 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार, अमेरिका में गेहूं के कुल फार्म की संख्या 2002 के 1,69,528 से घटकर 2022 में 97,014 रह गई। यानी इसमें 40 प्रतिशत से अधिक की गिरावट। विपणन वर्ष 2017-18 से 2023-24 के बीच बुवाई का क्षेत्र 4 करोड़ एकड़ से नीचे बना रहा, जबकि 2008-09 में यह 5.6 करोड़ एकड़ था।

गेहूं के रकबे में गिरावट व्यापक फसल संतुलन बदलाव का हिस्सा है। मक्का का क्षेत्र 9.53 करोड़ एकड़ आंका गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत कम है। यह गिरावट इलिनॉय, आयोवा, नेब्रास्का और डकोटा जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में कम बुवाई के कारण है।

इसके विपरीत, सोयाबीन का रकबा बढ़कर 8.47 करोड़ एकड़ होने का अनुमान है, जो 2025 की तुलना में 4 प्रतिशत अधिक है। मिडवेस्ट के अधिकांश हिस्सों में यह वृद्धि देखी जा रही है। यह बदलाव दर्शाता है कि किसान बदलती कीमतों और फसल चक्र (क्रॉप रोटेशन) के पैटर्न के अनुसार निर्णय ले रहे हैं और गेहूं व मक्का की तुलना में सोयाबीन को प्राथमिकता दे रहे हैं।

अन्य फसलों में ज्वार का क्षेत्र 61.2 लाख एकड़ रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से कम है, जबकि जौ (23.5 लाख एकड़) और जई (23.6 लाख एकड़) का रकबा लगभग स्थिर बना हुआ है। हालांकि इनका पैमाना छोटा है, फिर भी क्षेत्रीय स्तर पर इनका महत्व बना हुआ है।

इस रिपोर्ट को शुरुआती सीजन के रुझानों का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। यह रिपोर्ट बताती है कि कुल कृषि क्षेत्र लगभग स्थिर रहने के बावजूद उसकी संरचना बदल रही है। खासकर गेहूं लगातार आर्थिक और कृषि संबंधी दबावों के कारण पीछे होता जा रहा है।

हालांकि, यूएसडीए ने चेतावनी दी है कि अंतिम बुवाई के फैसले स्प्रिंग मौसम और बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेंगे। इसके बावजूद मौजूदा अनुमान स्पष्ट संकेत देते हैं कि अमेरिका में गेहूं का रकबा लगातार दबाव में है और 2026 इस गिरावट का ऐतिहासिक निचला स्तर साबित हो सकता है।

स्वामी विवेक जैन, प्रकाशक, विवेक जैन, मुद्रक कैलाश महाजन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित एवं 26/1, विवेकानंद कॉलोनी, वार्ड नंबर 5, खरगोन, जिला खरगोन से प्रकाशित, पिननं. 451001 (मप्र) संपादक विवेक जैन, RNI No. MPHIN/ 2022/85285. मोबा. नं. 9826225025, 94254 89337 (सभी विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)